भारत सरकार

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 787

24, जुलाई 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

अमृतसर शहर में बुनियादी ढांचे का विकास

†787. श्री गुरजीत सिंह औजलाः

क्या **आवासन और शहरी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार अमृतसर के अंतर्राष्ट्रीय महत्व को ध्यान में रखते हुए इसे विश्वस्तरीय सड़क अवसंरचना के साथ एक आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और पर्यटन केंद्र के रूप में एक अत्याधुनिक शहरी क्षेत्र के तौर पर विकसित करने जा रही है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार श्री गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से स्वर्ण मंदिर तक और अन्य प्रमुख प्रवेश बिंदुओं और पर्यटन क्षेत्रों को कवर करते हुए विशिष्ट फ्लाईओवर, एलिवेटेड कॉरिडोर और स्मार्ट सड़कों के निर्माण सहित एक समर्पित अवसंरचना विकास योजना को मंजूरी देगी और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार भारतमाला या स्मार्ट सिटी पहल के तहत अमृतसर के लिए एक विशेष शहरी परिवहन कॉरिडोर परियोजना शुरू करने पर विचार करेगी; और

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा और इस संबंध में समय-सीमा क्या है और यदि नहीं, तो क्या सरकार अमृतसर में सुचारु शहरी यातायात और शहर के सौंदर्यपूर्ण सुधार की लंबे समय से चली आ रही मांग पर विचार करेगी और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री

(श्री तोखन साहू)

(क) से (घ): सातवीं और बारहवीं अनुसूचियों के साथ संविधान के अनुच्छेद 243डब्ल्यू के प्रावधानों के अनुसार, शहरी विकास से संबंधित मामले राज्यों/शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। हालांकि, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (एमओएचयूए) अपने प्रमुख मिशनों/कार्यक्रमों जैसे अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत) और अमृत 2.0, स्वच्छ भारत मिशन-शहरी (एसबीएम-यू) और एसबीएम-यू

2.0, स्मार्ट सिटीज मिशन (एससीएम), प्रधान मंत्री आवास योजना-शहरी (पीएमएवाई-यू) और पीएमएवाई-यू 2.0, शहरी परिवहन (यूटी), आदि के माध्यम से राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों(यूटी) को उनके शहरी विकास एजेंडे में कार्यक्रम संबंधी सहायता प्रदान करता है।
इन मिशनों/योजनाओं के माध्यम से, केंद्र सरकार राज्य योजनाओं को अनुमोदन देती है और राज्यों को केंद्रीय सहायता (सीए) प्रदान करती है। इन परियोजनाओं का चयन, डिजाइन, अनुमोदन और क्रियान्वयन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों और शहरों/जिलों द्वारा किया जाता है।

स्मार्ट सिटी मिशन (एससीएम) के तहत, 100 शहरों में रेट्रोफिटिंग, पुनर्विकास और ग्रीनफील्ड विकास के माध्यम से क्षेत्र-आधारित विकास दृष्टिकोण अपनाया जाता है। 11.07.2025 की स्थिति के अनुसार, अमृतसर ने स्मार्ट सिटी मिशन (एससीएम) के तहत 1,911 करोड़ रुपए की लागत की सड़क परियोजनाओं सहित कुल 44 परियोजनाएं शुरू की हैं। इनमें से 1800 करोड़ रुपये की 41 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं। स्मार्ट मोबिलिटी के लिए, स्मार्ट सिटी मिशन के तहत अमृतसर द्वारा 244 करोड़ रुपए की 9 परियोजनाएं शुरू की गई हैं, जिनमें से 197 करोड़ रुपए की 8 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं।

इसके अतिरिक्त, भारत सरकार ने पीपीपी मॉडल पर 10,000 इलेक्ट्रिक बसें चलाकर सिटी बस संचालन को बढ़ाने के उद्देश्य से 16 अगस्त 2023 को "पीएम-ई-बस सेवा योजना" की, शुरुआत की है। इस योजना के अंतर्गत 10 वर्षों के लिए प्रति किलोमीटर बस परिचालन संबंधी केन्द्रीय सहायता (सीए) सहित संबद्ध अवसंरचना (अर्थात बिहाइंड द मीटर बिजली और बस डिपो अवसंरचना) के विकास के लिए एकमुश्त केन्द्रीय सहायता भी प्रदान की जाती है।

पीएम-ई-बस सेवा योजना के अंतर्गत, पंजाब राज्य के लिए 347 ई-बसें स्वीकृत की गई हैं, जिनमें अमृतसर के लिए 100 ई-बसें शामिल हैं और संबद्ध अवसंरचना के विकास के लिए पंजाब को 18.06 करोड़ रुपये की पहली किश्त जारी की गई है, जिसमें अमृतसर के लिए 5.05 करोड़ रुपये शामिल हैं।

इसके अतिरिक्त, यह ध्यान मे रखते हुए कि अमृतसर विरासत, संस्कृति और सामाजिक-धार्मिक महत्व के संबंध में देश के सबसे प्रमुख शहरों में से एक है, भारत सरकार ने यात्रा के अनुभव को बढ़ाने और सड़क मार्ग से अमृतसर आने वाले पर्यटकों की सुविधा में सुधार करने के लिए कई उपाय किए हैं।

सड़क, परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा अमृतसर और उसके आसपास, कुछ महत्वपूर्ण राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजनाएँ जैसे कि अमृतसर से संपर्क के लिए स्पर सहित दिल्ली-अमृतसर-कटरा एक्सप्रेसवे, अमृतसर बाईपास (अटारी-वाघा सीमा तक आगंतुकों की आवाजाही

को सुगम बनाने के लिए), अमृतसर-रामदास कॉरिडोर (करतारपुर साहिब जाने वाले पर्यटकों की सुविधा के लिए), अमृतसर-ऊना कॉरिडोर (अमृतसर को आनंदपुर साहिब से जोड़ने वाला) और ब्यास-बटाला-डेरा बाबा नानक कॉरिडोर (ब्यास को करतारपुर साहिब कॉरिडोर से जोड़ने वाला) परियोजनाए शुरू की गई हैं और कार्यान्वित की जा रही हैं।

*****